

राजनीतिक प्रस्ताव

शहीदों को श्रद्धांजलि

1998 में सम्पन्न चौथे सम्मेलन के बाद से हमारे देश में शासक वर्ग की सत्ता और शोषकों की गुण्डावाहिनियों का मुकाबला करते हुए कम्युनिज्म के उच्च आदर्शों के लिए बहुत सारे कम्युनिस्टों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आंध्र-प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और देश के अन्य हिस्सों में अनेक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी दुश्मन की गोलियों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए हैं।

नेपाल में राजशाही के विरुद्ध जनवादी क्रांति को आगे बढ़ाने में बहुत सारे कम्युनिस्टों और जांबाज जन-योद्धाओं ने अपने प्राणों को उत्सर्ग किया है। पेरु, फिलीपीन्स, तुर्की और दुनिया के अन्य हिस्सों में साम्राज्यवाद एवं शोषक वर्गों की सत्ता के विरुद्ध संघर्ष के दौरान बहुत सारे कम्युनिस्ट एवं मेहनतकश लोग शहीद हुए हैं। फिलिस्तीन में इज़रायली-जियनवादी सत्ता के आक्रमण के विरुद्ध स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र के लिए कम्युनिस्टों एवं साम्राज्यवाद-विरोधी, जियनवाद-विरोधी सैकड़ों लोगों ने कुर्बानी दी है।

साम्राज्यवाद-पूंजीवाद एवं शोषक वर्गों के शोषण-उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष करते हुए दुनिया भर में हजारों मजदूर और मेहनतकश वर्ग के लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है।

भारत की कम्युनिस्ट लीग (मा० ले०) का पांचवां सम्मेलन इन सभी कम्युनिस्टों और मेहनतकश वर्ग के शहीदों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यह सम्मेलन इन शहीदों की याद में अपने लाल झण्डे को झुकाता है। सम्मेलन दृढ़संकल्प व्यक्त करता है कि शहीदों की कुर्बानी के दुख को शक्ति में बदलकर मौजूदा अन्यायकारी, शोषणकारी व्यवस्था को ध्वस्त करने के संघर्ष को आगे बढ़ाकर, कम्युनिज्म के उच्च आदर्शों को हकीकत में बदलने का संग्राम तेज करेगा।



माक्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा जिन्दाबाद !

विचारधारा का महत्व :

आज से लगभग एक शताब्दी पूर्व लेनिन ने कहा था “क्रांतिकारी सिद्धांत के बिना क्रांतिकारी आंदोलन असंभव है”। लेनिन के ये शब्द क्रांतिकारी सिद्धांत के महत्व को या दूसरे शब्दों में कहा जाय तो सही विचारधारा की आवश्यकता को स्पष्ट तौर पर सामने ला देते हैं।

सही विचारधारा से आशय उस विचारधारा से है जो सर्वहारा वर्ग के हितों को अभिव्यक्त करती हो तथा वर्ग-विहीन, शोषण-विहीन समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करती हो।

सामाजिक व्यवहार की कसौटी पर खरी उतरने वाली विचारधारा ही अपने युग में मौजूद प्रश्नों का वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत कर सकती है तथा उन प्रश्नों और समस्याओं के व्यावहारिक समाधान के मार्ग को सुझा सकती है।

निस्संदेह सामाजिक व्यवहार के दौरान ही क्रांतिकारी सिद्धांत या विचारधारा विकसित और समृद्ध होती है।

सर्वहारा वर्ग की पार्टी-कम्युनिस्ट पार्टी के लिये सदा से, क्रांतिकारी सिद्धांत या सही विचारधारा का प्रश्न केन्द्रीय महत्व का प्रश्न रहा है। यह अनायास नहीं है कि मार्क्स से लेकर माओ तक ने गैर सर्वहारा विचारों से अपने जीवन काल में दुर्धर्ष संघर्ष किये और क्रांतिकारी सिद्धांत की रक्षा की और उसे समृद्ध किया। यह अनायास नहीं है कि सभी गद्दार, भगोड़े, बुर्जुआ चाटुकार क्रांतिकारी सिद्धांत की कालजयी सच्चाई के कारण उसका सामना करने से घबराते हैं और सर्वहारा वर्ग को क्रांतिकारी सिद्धांत से दूर रखने के लिए एड़ी-चोटी जोर लगा देते हैं। यह अनायास नहीं है कि बुर्जुआ वर्ग क्रांतिकारी सिद्धांत से कांपता है और संशोधनवाद को पूरे दिल से पुचकारता है।

हमारे समय का माक्सवाद :

हमारा समय ‘साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रांतियों’ का समय है। हमारे समय की सही विचारधारा, माक्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा है। माक्सवाद ही वह क्रांतिकारी सिद्धांत है, जिसने उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध तथा पूरी बीसवीं सदी में क्रांतिकारी आंदोलनों को जन्म दिया तथा मानव जाति के इतिहास के तीन महान प्रयोगों से सर्वहारा वर्ग को महान शिक्षा देते हुये, उसके शोषण-विहीन, वर्ग-विहीन समाज बनाने के लक्ष्य के मार्ग को आलोचित किया। इस दौरान स्वयं माक्सवाद विकसित और समृद्ध होकर माक्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा के स्तर तक जा पहुंचा।

ये तीन महान प्रयोग थे:- 1871 का पेरिस कम्यून, 1917 की अक्टूबर क्रांति व उसके बाद समाजवाद का निर्माण तथा तीसरा महान प्रयोग, माओ व चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा का शस्त्रागार उन तमाम सार्वभौमिक महत्व के सिद्धांतों से भरा हुआ है जो सर्वहारा को वर्तमान वर्गीय समाज से वर्ग-विहीन समाज के निर्माण का रास्ता दिखाते हैं। मार्क्सवादी चिंतकों-मार्क्स-एंगेल्स-लेनिन-स्टालिन-माओ द्वारा समय-समय पर किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों के मूल्यांकन, आकलन, अनुमान अथवा किसी देश विशेष के लिए, काल विशेष में, क्रांति के कार्यक्रम, वर्गों की लामबन्दी, रणकौशल व पथ इत्यादि का महत्व सार्वभौमिक नहीं है। अतः सर्वहारा विचारधारा के तहत द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग-संघर्ष के सिद्धांत, बेशी मूल्य की अवधारणा, पूंजीवाद तथा उसकी उच्चतम अवस्था साम्राज्यवाद की सामान्य आलोचना, राजसत्ता के वर्गीय चरित्र की व्याख्या, सर्वहारा वर्ग की पार्टी (कम्युनिस्ट पार्टी) की अवधारणा, सर्वहारा तानाशाही की अवधारणा, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच एक संक्रमणकालीन समाज (समाजवाद) की अवधारणा, पूंजीवादी पुनर्स्थापना से बचने के लिये समाजवाद में वर्ग-संघर्ष एवं महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की अवधारणा इत्यादि तो सर्वहारा विचारधारा के अभिन्न अंग हैं, परन्तु ऐसे मूल्यांकन कि भारत का ग्रामीण समाज सामन्तवादी नहीं था या यह कि पिछड़े देशों की क्रांति का कार्यक्रम नवजनवादी क्रांति होगा तथा इसमें दीर्घकालिक लोक युद्ध द्वारा विजय हासिल की जा सकती है इत्यादि, कम या ज्यादा तथ्यों पर आधारित तत्कालीन मूल्यांकन हैं जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर बदलना उचित होता है। इन्हें सार्वभौमिक महत्व की चीजें नहीं माना जा सकता। ये मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा का अंग नहीं हैं हालांकि इन्हें जानकर बहुत कुछ सीखा-समझा जा सकता है।

हमारे समय में मार्क्सवाद की बुनियादी प्रस्थापनाओं पर बुर्जुआ वर्ग तथा संशोधनवादियों द्वारा चौतरफा हमला बोला जा रहा है। बुर्जुआ वर्ग जहां कुत्साप्रचार का सहारा लेकर मार्क्सवाद को बदनाम करने के कोशिश कर रहा है, वहीं संशोधनवादी मार्क्सवाद को देश/काल परिस्थिति के अनुरूप बनाने के नाम पर सर्वहारा वर्ग के खिलाफ षडयंत्र कर रहे हैं। यह एक सच्चाई रही है कि मार्क्सवाद को सबसे अधिक नुकसान भीतरघातियों ने पहुंचाया है मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन और माओ अपने जीवनकाल में मार्क्सवाद पर किये जाने वाले बुर्जुआ आक्रमणों तथा भीतरघाती संशोधनवादियों के षडयंत्रों का माकूल जवाब देते रहे हैं और सर्वहारा वर्ग की विचारधारा की रक्षा करते हुये, उन्होंने इस वैज्ञानिक विचारधारा को लगातार विकसित किया है।

आज समाज में, तमाम गैर-सर्वहारा विचारधारयें मौजूद हैं जो सर्वहारा तथा मेहनतकशों के संघर्ष को पीछे धकेल रही हैं और क्रांतिकारी पांतों में विभिन्न किस्म के भ्रमों को जन्म दे रही हैं। इनमें से कई मार्क्सवाद-जिन्दाबाद! और लेनिनवाद-मुर्दाबाद! कई मार्क्सवाद-लेनिनवाद जिन्दाबाद! लेकिन स्टालिन-मुर्दाबाद! कई मार्क्स-लेनिन-स्टालिन-जिन्दाबाद! लेकिन माओ मुर्दाबाद! का नारा लगाती हैं। आज के संशोधनवादियों और बुर्जुआ चाटुकारों को सबसे अधिक नफरत स्टालिन और माओ से है, स्टालिन और माओ के खिलाफ ही मुख्य मोर्चा आजकल इन्होंने खोला हुआ है। साम्राज्यवादियों से लेकर सभी संशोधनवादी, जो कि सर्वहारा वर्ग के दुश्मन हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले स्टालिन और बाद में माओ ही थे जिन्होंने मार्क्स-एंगेल्स और लेनिन की क्रांतिकारी शिक्षा की हिफाजत की और उसे व्यवहार में उतार कर उसे और अधिक उन्नत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे स्टालिन और माओ ही थे जिन्होंने साम्राज्यवादियों को पीछे हटने के लिए बाध्य किया तथा संशोधनवादियों के घृणित मंसूबों का सर्वहारा वर्ग के सामने पर्दाफाश किया।

सर्वहारा वर्ग के दुश्मन भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वे स्टालिन ही थे जिनके नेतृत्व में लेनिन की मृत्यु के बाद पहले समाजवादी राज्य का कुशलतापूर्वक निर्माण हुआ और वे ही थे जिनके नेतृत्व में द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से इन्सानियत को बचाया जा सका। बाकी साम्राज्यवादी तो अपने घृणित हितों की सुरक्षा तथा मुनाफा बटोरने में ही लगे रहे। वे स्टालिन ही थे जिनके नेतृत्व में फासीवाद और नाजीवाद को करारी शिकस्त दी गई। सच तो यह है कि स्टालिन और माओ ही थे जिन्होंने राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष का भरपूर समर्थन किया और उन्हें समयोचित सलाह मशविरा तथा सहयोग दिया।

स्टालिन की मृत्यु के बाद वे माओ ही थे जिन्होंने सर्वहारा के लाल झण्डे को बुलन्द रखा तथा जब स्टालिन पर सवाल खड़े किये जाने लगे तो उन्होंने स्टालिन का सटीक मूल्यांकन कर, उनके कार्यों के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया तथा उनकी भूलों से सबक लेते हुए, संशोधनवादी हो चुकी सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ 'महान बहस' का सूत्रपात किया। उन्होंने आधुनिक संशोधनवादियों खुश्चेव व ब्रेझनेव के खिलाफ निर्मम संघर्ष छेड़ा तथा पूंजीवादी पुनर्स्थापना को रोकने के लिए महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का उद्घोष किया। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति ने सर्वहारा वर्ग के समक्ष उन सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर सर्वहारा वर्ग पूंजीवाद की पुनर्स्थापना के खतरे से निपटते हुए, समाजवाद के निर्माण को जारी रख सकता है तथा मानव जाति के महान लक्ष्य साम्यवादी समाज की स्थापना की ओर निरन्तर अग्रसर हो सकता है।

आज मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा से भटकाव, विच्युति तथा संशोधन के रूप में ढेर सारी गैर-सर्वहारा विचारधारयें समाज में सक्रिय हैं तथा अपना प्रभाव रखती हैं। इनकी एक लम्बी शृंखला है। इनमें से कुछ पुराने संशोधनवादी हैं जिनके विचारों का प्रभाव अभी तक बना हुआ है तथा इनके अनुयायी यत्र-तत्र बिखरे हुये हैं। इनमें त्रात्स्की-पंथी सर्वप्रमुख हैं।

दुनिया में आज भी जिन संशोधनवादियों का प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा आंदोलन में सबसे अधिक है वो खुश्चेवपंथी हैं। इनकी ही आधुनिक कड़ी डेंग-श्याओ-पिंग से जा कर जुड़ती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आज दुनिया भर के संशोधनवादी कम्युनिस्टों की रहनुमा बनी हुई है। सोवियत संघ के ध्वस्त होने के बाद रूसी संशोधनवादियों का प्रभाव जहां सीमित हुआ वहीं चीनी संशोधनवादी सर्वहारा क्रांतिकारी आंदोलन के सबसे बड़े शत्रु बन कर उभरे हैं।

गैर-सर्वहारा विचारधारा के एक बड़े प्रतिनिधि के रूप में उन देशों के नेता उभरे हैं जहां एक समय साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रीय क्रांतियां हुयीं और जनता के जनवाद (पीपुल्स डेमोक्रेसी) कायम हुए, इन देशों के नेताओं और पार्टियों ने सोवियत संशोधनवादियों के खिलाफ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्ष के समय दुलमुल रवैया अपनाया। अपने राष्ट्रीय हितों की खातिर सोवियत संशोधनवादियों से समझौतापरस्ती का रूख अपनाते हुये इन्होंने अवसरवाद का परिचय दिया। माओ द्वारा चीन में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना के खतरे से निपटने के लिए की गई महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के पक्ष में इन्होंने अवस्थिति नहीं ली। अन्ततः ये अपने देशों में समाजवाद कायम करने के स्थान पर राजकीय पूंजीवाद की ही स्थापना कर सके। कास्त्रो, किम-इल-सुंग, ले-दुआन इस धारा के प्रतिनिधि हैं।

सोवियत संघ के खुश्चेव व अन्य संशोधनवादियों के खिलाफ अवस्थिति ग्रहण करने वाले, परन्तु माओ विचारधारा को न मानने वाले अल्बानियाई लेबर पार्टी के नेता अनवर होजा के विचारों का प्रभाव भी अन्तर्राष्ट्रीय

स्तर पर मौजूद है। चेग्वेरा की वामदुस्साहसवादी, नायकवादी गैर-सर्वहारा विचारधारा का प्रभाव लातिन अमेरिका तथा अफ्रीका के कई मुल्कों में मौजूद है।

उपरोक्त प्रमुख गैर-सर्वहारा विचारधाराओं के अतिरिक्त ढेर सारे बुद्धिजीवी, संगठन सीमित स्तर पर ही सही, सर्वहारा की कतारों में भ्रमों व विच्युतियों को जन्म देते हैं। इन सभी के खिलाफ मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा के क्रांतिकारी सिद्धांत की स्थापना आवश्यक है, इनके खिलाफ निर्मम विचारधारात्मक संघर्ष चलाकर ही सर्वहारा की पांतों को क्रांतिकारी सिद्धांत के इर्द-गिर्द लामबन्द किया जा सकता है।

पिछले दो दशकों से क्रांतिकारी पातों में एक अनावश्यक विवाद, माओ-विचारधारा, को माओवाद कहा जाय या न कहा जाय, उठ खड़ा हुआ है। माओ विचारधारा माओ के जीवन काल में क्रांतिकारी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अपनायी गई शब्दावली है जो माओ तथा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की सार्वभौमिक अवधारणा को अपने में समेटे हुये है। इस अनावश्यक विवाद से उत्पन्न होने वाले भ्रमों से हमें क्रांतिकारी पांतों को बचाना चाहिए तथा पहले से स्वीकृत शब्दावली का ही प्रयोग करते हुये उसे माओ-विचारधारा ही कहना चाहिये।

मार्क्सवाद की कुछ बुनियादी अवधारणाओं पर नया हमला:

दुनिया की क्रांतिकारी कतारों के लिए पिछले कई दशकों से यह स्पष्ट रहा है कि सोवियत संघ में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना 1956 में ही हो चुकी थी तथा 1968 आते-आते वह सामाजिक साम्राज्यवादी देश में तब्दील हो चुका था। सोवियत संघ के साथ पूर्वी यूरोप के अधिकांश लाल देशों का रंग भी पीला पड़ चुका था। इसी तरह माओ की मृत्यु के बाद चीन भी पूंजीवादी मार्ग को पकड़ चुका था। आज दुनिया की तमाम क्रांतिकारी शक्तियां जानती हैं कि दुनिया में कोई भी समाजवादी देश नहीं है, कहीं भी सर्वहारा की सत्ता नहीं है। समाजवादी खेमा बिखर चुका है। परन्तु नब्बे के दशक में सोवियत साम्राज्यवाद के पतन तथा पूर्वी यूरोप के घटनाक्रम को साम्राज्यवादी देशों के नेताओं और उनके बुद्धिजीवियों ने समाजवाद की पराजय के बतौर प्रचारित किया तथा इनके सुर में तीसरी दुनिया के पूंजीपति वर्ग के बुद्धिजीवियों और शासकों ने भी अपना सुर मिलाया।

इसके साथ ही प्रकट हुआ उत्तर आधुनिकतावाद। बीसवीं सदी के अन्त में जन्मी यह विचारधारा अपने नग्न रूप में पूंजीवादी विचारधारा है, परन्तु शब्दचतुर्य के द्वारा यह ऐसे प्रदर्शित करती है मानो यह वर्गोपरि विचारधारा हो। वर्गीय समाज में वर्गोपरि कोई विचारधारा नहीं हो सकती है। वह किसी न किसी वर्ग की सेवा अवश्य करती है। उत्तर आधुनिकतावाद सर्वहारा के दर्शन द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की खिलाफत करता है और मार्क्सवाद पर सर्वसत्तावाद (Totalitarianism), अपचयनवाद (Reductionism), सार्वभौमिकतावाद (Universalism) का आरोप लगाता है। यह द्वन्द्वात्मक प्रणाली के स्थान पर अधिभूतवादी प्रणाली तथा भौतिकवाद के स्थान पर भाववाद को स्थापित करता है। प्रकृति, समाज, घटना-परिघटनाओं का वर्णन करते समय यह शब्दजाल का प्रयोग करते हुये निकृष्ट किस्म के सार-संग्रहवाद में तब्दील होकर ऐतिहासिक भौतिकवाद की खिलाफत करता है और पूंजीपति वर्ग की सेवा करता है। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध से उत्तर आधुनिकतावादियों, पतित समाजवादियों तथा बुर्जुआ बुद्धिजीवियों ने हल्ला मचाया 'क्रांतियां मर चुकी हैं', 'विचारधारा का अंत हो चुका है' इत्यादि। इन रात के

पिशाचों, सियारों, चमगादड़ों ने इसके साथ मार्क्सवाद की कड़े सामाजिक संघर्षों में स्थापित तमाम बुनियादी अवधारणों पर जमकर हल्ला बोल दिया। लेनिन, स्टालिन की प्रतिमाओं को धूल में मिलाकर इन्होंने शोर मचाया कि वे निर्णायक तौर पर विजयी हो गये हैं, हालांकि इसका विश्वास स्वयं उन्हें भी नहीं है।

उत्तर आधुनिकतावादियों का साथ देने में संशोधनवादी, पराजित मानसिकता वाले शंकालु बुद्धिजीवी, मौलिक चिंतन के तमाम मसीहा, कम्युनिस्ट कतारों के भीतरघाती और गद्दारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जोर-शोर से इनका साथ देना शुरू किया। 'नई परिस्थितियां,' 'खुला सवाल' आदि कहकर इन्होंने कम्युनिस्ट कतारों तथा सर्वहारा वर्ग में भ्रम फैलाने की भरसक कोशिश की है। सारे मरे हुये चूहों को प्रेत-आत्मायें अपनी देव प्रतिमाओं का निर्माण कर सर्वहारा वर्ग को यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि वे उसके नये उद्धारक हैं, कि क्रांतियों को जमाना बीत गया है, वर्ग धूमिल पड़ गये हैं अब उनके 'नये सामाजिक आंदोलन' ही सर्वहारा वर्ग की जो भी मुक्ति है, उसे ला सकते हैं।

इन विचारकों का केवल नाम ही नया है वरना इनके काम और विचार पुराने पिटे हुये संशोधनवादियों के ही कुकृत्यों का जारी रूप हैं।

एक जमात दुनिया में ऐसे नमूनों की पैदा हो गई है जिनका कहना है कि मार्क्स द्वारा परिभाषित वर्गीय समाज की बात पुरानी पड़ चुकी है और वर्गीय संरचना उनकी तथाकथित सामाजिक संरचना के नीचे दब गयी है। अतः वर्ग के स्थान पर सामाजिक पहचानों यथा नस्ल, जाति, स्त्री, आदिवासी इत्यादि के आधार पर नये सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया जाय। इस जमात के नमूनों ने वर्ग को सामाजिक पहचान से, वर्ग-संघर्ष को वर्गीय सहयोग वाले नये सामाजिक आंदोलन से, सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद को नये 'अंतर्राष्ट्रीयतावाद' से प्रतिस्थापित कर दिया है। अपने आग्रहों, धारणाओं तथा नयी सामाजिक परिस्थितियों का हवाला देने वाले ये नमूने खुलकर यह नहीं बताते कि यह समाज कौन सा है? इसमें उत्पादन सम्बन्ध क्या हैं? शोषक और शोषित वर्ग कौन हैं? उत्पादन की प्रणाली कौन सी है? राज व्यवस्था का उत्पीड़क चरित्र क्यों है?

उत्तर आधुनिकतावादियों की इन सिरफिरी बातों के साथ मार्क्सवाद पर आज भी हमला करने वालों में संशोधनवादी तथा दक्षिणपन्थी भटकावों का शिकार हुये मार्क्सवादियों की संख्या अधिक है ये सर्वहारा तानाशाही की अवधारणा पर सवाल उठाते हैं और स्टालिन की निन्दा करते हुये अपने आपको जनवाद के बड़े पक्षधर साबित करते हैं। सर्वहारा तानाशाही के विस्तार को जनवाद की दुहाई देते हुये ये चुपके से बुर्जुआ जनवाद अर्थात् बुर्जुआ तानाशाही में बदल देते हैं। और कहते हैं कि एक पार्टी—कम्युनिस्ट पार्टी—के स्थान पर समाजवाद में बहु-पार्टी व्यवस्था होनी चाहिये।

पार्टी की लेनिनवादी अवधारणाओं को भी सर्वहारा वर्ग के दुश्मन और गद्दार बदल रहे हैं। लेनिन की तमाम बार कसम खाने के बाद ये लेनिन द्वारा प्रस्तुत अवधारणाओं की हत्या करने के प्रयास करते हुये कहते हैं कि लेनिन की बातों को यांत्रिक ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए इत्यादि, दूसरे इण्टरनेशनल के पतन से लेकर बाद के इतिहास ने यह साबित कर दिया है कि लेनिन की बातों को "यांत्रिक" ढंग से न लेने के कारण ही तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां संशोधनवादी या बुर्जुआ पार्टियों में तब्दील हो गईं, इंकलाब करने में अयोग्य साबित हुयीं। ये गद्दार, गुप्त पार्टी के स्थान पर खुली पार्टी, जनवादी-केन्द्रीयता के स्थान पर सिर्फ जनवाद, पेशेवर क्रांतिकारियों के स्थान पर ज्यादा क्षमतावान लोगों की पार्टी आदि की बातें करते हुये मेन्शेविकों की औलाद ही साबित होते हैं। ये

लेनिनवाद के बुनियादी सांठनिक उसूलों की हत्या करने का प्रयास करते हैं और सर्वहारा वर्ग को उसके अचूक हथियार कम्युनिस्ट पार्टी से महरूम कर बुर्जुआ वर्ग के लायक सेवक बनना चाहते हैं।

संशोधनवाद के इन नये चैंपियनों को सर्वहारा तानाशाही के अलावा जिस अवधारणा से आज सबसे ज्यादा दिक्कत है, वह है—महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति। चीन के संशोधनवादी और सर्वहारा वर्ग के गद्दार तो महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति को महान विपदा बताते रहे हैं। साम्राज्यवादी और बुर्जुआ सिद्धांतकार भी इसको, इसी तरह व्यक्त करते रहे हैं। सांस्कृतिक क्रांति के काल को 'आंतक राज' 'अराजकता' आदि कह कर संबोधित किया जाता रहा है। सोवियत-संघ तथा पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना के साथ, साम्राज्यवाद तथा इन देशों का बुर्जुआ अपनी सफलता पर प्रसन्न हो रहा था, परन्तु चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ ने इसका समाधान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने मार्क्स-एंगेल्स और लेनिन की शिक्षाओं का रचनात्मक ढंग से विकास किया, पेरिस कम्यून के महान प्रयोगों से सीखा तथा द्वन्द्वात्मक-भौतिकवाद का सृजनात्मक ढंग से प्रयोग कर सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की अवधारणा प्रस्तुत की और चीनी समाज में उसको व्यवहार में उतारा। माओ के इस महान अवदान के कारण ही दुनिया के क्रांतिकारी माओ विचारधारा का इतने अधिक सम्मान के साथ जिक्र करते हैं। दुनिया भर के गद्दार संशोधनवादी छद्म कम्युनिस्ट भी इसी कारण महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की इतनी लानत-मलानत करते हैं। सच भी है महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति बुर्जुआ वर्ग के लिये महान विपदा बनाकर ही आई थी।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा की बुनियादी अवधारणाओं पर प्रश्न खड़े करके, धूर्त बुर्जुआ बुद्धिजीवी अपने घृणित उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते हैं। साम्राज्यवादियों, संशोधनवादियों, उत्तर-आधुनिकतावादियों के घृणित मंसूबों को कभी भी क्रांतिकारी कम्युनिस्ट और सर्वहारा वर्ग कामयाब नहीं होने देगा। संशोधनवादियों और पगलाये हुये साम्राज्यवादियों के आक्रमण के बाद हमेशा ही मार्क्सवाद और अधिक ऊर्जावान, प्राणवान तथा शक्तिवान हुआ है, इस बार भी ऐसा ही होगा। सर्वहारा वर्ग अपनी पार्टी के नेतृत्व में क्रांतिकारी सिद्धांत का प्रयोग कर दुनिया में पुनः सर्वहारा तानाशाही को स्थापित करेगा। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का प्रयोग करते हुये पूंजीवाद की पुनर्स्थापना के खतरे से लड़ेगा तथा शोषण-विहीन, वर्ग-विहीन समाज की स्थापना की ओर निरन्तर अग्रसर होता जायेगा।

भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन में मौजूद दो गैर-सर्वहारा प्रवृत्तियां:

भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन आज संकट के दौर से गुजर रहा है। दक्षिणपंथी अवसरवाद का खतरा मुख्य तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के समक्ष खड़ा है। अस्सी व नब्बे के दशक में एक-एक करके कई क्रांतिकारी संगठन दक्षिणपंथ की ओर झुके, विचारधारात्मक अवसरवाद का परिचय देते हुये अंततः वे संशोधनवादी संगठनों में तब्दील होकर बुर्जुआ वर्ग की पांतों में शामिल हो गये।

समाजवाद की वक्ती पराजय, साम्राज्यवाद के आक्रामक होने तथा भारतीय शासक वर्ग को क्रांतिकारी ताकतों से कोई गम्भीर चुनौती न मिलने के कारण जहां पहले ही भारतीय सर्वहारा वर्ग और मेहनतकश अवाम भीषण संकटों का सामना कर रहा था, वहीं दक्षिणपंथी अवसरवाद के बढ़ते हुये रूझानों ने क्रांतिकारी पांतों को

दीमक की तरह चाटना जारी रखा है। विचारधारात्मक स्तर पर यह अवसरवाद क्रांतिकारी पातों के बीच तमाम किस्म के विभ्रमों को जन्म दे रहा है। अतः इसके खिलाफ विचारधारात्मक स्तर पर निर्मम संघर्ष की आवश्यकता है। भारतीय कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन में दक्षिणपंथी अवसरवाद की प्रमुख अभिव्यक्तियां इस प्रकार हैं:

- ★ मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा को अपने कार्यों के मार्गदर्शक क्रांतिकारी सिद्धांत के रूप में, औपचारिक तौर पर तो स्वीकारना परन्तु आचरण में ढुलमुलपन दिखलाना।
- ★ सोवियत संघ में 1956 में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना के तथ्य को स्वीकारने में हिचकिचाहट दिखाना तथा साम्राज्यवादियों तथा संशोधनवादियों की तरह तो नहीं लेकिन कई सारे, किन्तु-परन्तु के साथ यह कहना कि सोवियत संघ में किसी न किसी रूप में 1990 तक समाजवाद था। सोवियत संघ के सामाजिक साम्राज्यवादी चरित्र को नजरअंदाज करना।
- ★ इसी तरह आज के चीन में हो रहे परिवर्तनों को चीनी समाजवादी प्रयोगों के किसी सिलसिले के बतौर लेना और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में सही और गलत के प्रति ढुलमुलपन दिखलाना।
- ★ सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के विचारधारात्मक पक्ष तथा पूंजीवादी पुनर्स्थापना रोकने में माओ विचारधारा के महत्वपूर्ण योगदान पर दृढ़ता से न खड़ा होना या उसे संदेह की निगाहों से देखना।
- ★ सर्वहारा अधिनायकत्व को बनाये रखने, समाजवादी समाज का निर्माण करने तथा फासीवाद को निर्णायक तौर पर शिकस्त देने में स्टालिन की महान भूमिका को उनकी भूलों-गलतियों के समक्ष खड़ा करना तथा उनके मूल्यांकन में माओ की लाइन को न अपनाना, बल्कि स्वतंत्र चिंतन करना।
- ★ सर्वहारा तानाशाही के युग के प्रति, जो कि पूंजीवादी समाज से साम्यवादी समाज के बीच का संक्रमणकालीन समाज है, जिसमें वर्ग व वर्ग-संघर्ष बने रहते हैं, ढुलमुल यकीनी दिखलाना तथा जनवाद के नाम पर सर्वहारा तानाशाही में नये विचारों की आवश्यकता बतलाते हुये अवसरवादी रूझानों को व्यक्त करना।
- ★ बुर्जुआ जनवाद अथवा परिस्थितियों का हवाला देते हुए गुप्त पार्टी की बोल्शेविक नीति को चुपके से या धीमे-धीमे व्यवहार में बदलना तथा सिद्धांतों में औपचारिक तौर पर स्वीकारते हुये भी, किन्तु-परन्तु करना।
- ★ भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में किसानों की भूमिका को बढ़ा-चढ़ा कर देखना तथा किसानों की दृष्टि से किसानों की समस्या को देखना, न कि सर्वहारा वर्ग के दृष्टिकोण से।
- ★ जाति, नारी, आदिवासी, राष्ट्रीयता, साम्प्रदायिकता, पर्यावरण आदि सवालों पर सर्वहारा अवस्थिति को दृढ़ता-पूर्वक ग्रहण करने के स्थान पर वर्गेतर दृष्टिकोण के भटकाव का शिकार होना।
- ★ अर्थवाद, ट्रेड-यूनियनवाद, कानूनवाद, सुधारवाद, स्वतःस्फूर्ततावाद की किसी न किसी किस्म से सचेत अथवा अचेत तौर पर प्रभावित होना तथा इन भटकावों के प्रति निर्मम संघर्ष न करना।
यद्यपि आज भारतीय कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन को दक्षिणपंथ से मुख्य खतरा है परन्तु “वामपंथी” भटकाव भी खतरे के बतौर मौजूद है। अक्सर दक्षिणपंथी के जवाब में “वामपंथी” भटकाव प्रारम्भ होते हैं।

दक्षिणपंथी भटकावों से लड़ने के दौरान “वामपंथी” भटकाव मजबूत होता है और यह दक्षिणपंथ से लड़ने के नाम पर होता है। भारतीय कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास इस बात का भी गवाह है कि “वामपंथी” भटकाव, कालान्तर में दक्षिणपंथी भटकाव में रूपांतरित हो जाते हैं। भारत में “वामपंथी” भटकाव की प्रमुख अभिव्यक्तियां इस प्रकार हैं :

- ★ जनदिशा का निषेध करना तथा “वामपंथी” आतंकवादी कार्य-दिशा को अपनाना। इस वजह से व्यापक मेहनतकश आबादी से कट जाना और हिरावलपंथी राजनीति का शिकार हो जाना मेहनतकश आबादी तथा सर्वहारा वर्ग को निष्क्रिय पदार्थ के बतौर लेना, जिनका मुक्ति कुछ वीर-नायकों द्वारा होगी, ऐसा मानना या ऐसा व्यवहार करना।
- ★ सशस्त्र संघर्ष को वर्ग-संघर्ष का एकमात्र रूप घोषित करना। समाज विशेष की परिस्थिति को ध्यान में रखने के बजाय सशस्त्र संघर्ष में क्रांतिकारी राजनीति तथा विचारधारात्मक संघर्ष को प्रतिस्थापित करना। क्रांतिकारिता को तय करने के लिए विचारधारा के स्थान पर सशस्त्र संघर्ष को मापदंड बनना। इसका परिणाम सारतः यह निकलता है कि सशस्त्र संघर्ष को निर्देशित करने के स्थान पर विचारधारा, राजनीति तथा वह क्रांतिकारी संगठन सभी उल्टे सशस्त्र संघर्ष से निर्देशित होने लगते हैं। सशस्त्र संघर्ष अपने आप में लक्ष्य बन जाता है।
- ★ व्यक्तिगत सफाये को वर्ग-संघर्ष का रूप मानना।
- ★ जनसंघर्षों, जनसंगठनों, जनआंदोलनों के महत्व को कम करके आंकना।
- ★ जनसंगठनों में विचारधारा व राजनीति को कृत्रिम और यांत्रिक तरीके से बिना जन-चरित्र का ख्याल रखे हुये आरोपित करना।
- ★ सर्वहारा वर्ग के सहयोगी वर्ग की भूमिका को या तो न स्वीकारना या कम करके आंकना।
- ★ कानूनी तरीके इस्तेमाल न करना, गैर-कानूनी कामों को कानूनी कामों से न मिला पाना। इस तरह के कार्यों को दक्षिणपंथी भटकाव मानना।

“वामपंथी” भटकाव भी दक्षिणपंथी भटकाव की तरह सर्वहारा वर्ग तथा मेहनतकश अवाम के बीच कई किस्म के भ्रमों को जन्म देता है। यह भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में संकीर्णतावाद, ग्रुप मानसिकता, हिरावलवाद, अनावश्यक हिंसा तथा अनावश्यक कुर्बानी, झूठे आशावाद, लकीर के फकीर जैसे तमाम भटकावों को जन्म देता रहा है। “वामपंथी” भटकावों ने अर्थवाद, सुधारवाद, संसदवाद जैसे तमाम दक्षिणपंथी भटकावों को भी कालान्तर में जन्म दिया है।

मार्क्सवाद व्यवहार का दर्शन है:

मार्क्सवादी विचारधारा का महत्वपूर्ण पक्ष है उसके सिद्धांतों को सामाजिक व्यवहार में उतारना तथा सर्वहारा वर्ग की सेवा करना। सर्वहारा वर्ग के हितों व लक्ष्यों के लिए समाज-व्यवस्था में हस्तक्षेप करना तथा समाज-व्यवस्था को बदलने के लिये आवश्यक रणनीति व रणकौशल को तय करना। समाज में मौजूद वर्ग-संघर्ष

को तीव्र करना तथा मौजूदा शासक-वर्ग की सत्ता को उलटकर सर्वहारा तानाशाही कायम करना, समाजवाद का निर्माण करते हुये साम्यवाद की ओर बढ़ना।

मार्क्सवादी दर्शन को मात्र चिंतन-मनन के धरातल पर बनाये रखना या उसके आधार पर केवल सामाजिक घटनाओं, परिघटनाओं पर बहस-मुबाहिसा करना मार्क्सवाद को किताबी ज्ञान में बदलना है, उसे निष्क्रियता के दलदल में धकेलना है। सामाजिक व्यवहार और प्रयोग से कटे हुए इस किस्म के मार्क्सवाद से भला सर्वहारा वर्ग के दुश्मनों को क्या आपत्ति हो सकती है ?

मार्क्सवाद के व्यवहार का पक्ष ही, इसे अब तक के सभी दर्शनों से अलग और अनूठा बना देता है। यह मात्र दुनिया को समझने का सिद्धांत न होकर दुनिया बदलने का सिद्धांत भी है। दुनिया बदलने के प्रयासों के दौरान ही मार्क्सवाद विकसित और उन्नत हुआ। सामाजिक व्यवहार में प्रत्यक्ष तौर पर लगे लेनिन, स्टालिन और माओ ने ही मार्क्सवाद को लेनिनवाद-माओ विचारधारा के स्तर पर पहुंचाया है।

मार्क्सवाद क्योंकि एक विज्ञान है इसलिए व्यवहार, प्रयोग के दौरान ही वह समृद्ध और विकसित हो सकता है और ऐसा ही हुआ भी है। मार्क्सवाद की सच्चाई इसी तरह से स्थापित भी हुई है।

बुर्जुआ वर्ग को मार्क्सवाद के सैद्धान्तिक पक्ष से तो आपत्ति है ही लेकिन व्यवहार से कटा मार्क्सवाद उसके लिए हानि रहित है। सामाजिक व्यवहार से नाभिनालबद्ध मार्क्सवाद उसके खिलाफ जंग का ऐलान है, बुर्जुआ समाज की मौत पर हस्ताक्षर है। यह अनायास नहीं है कि व्यवहार से कटे हुए कई मार्क्सवादी बुद्धिजीवी बुर्जुआ वर्ग के कृपापात्र बन रहे हैं जबकि व्यवहार में लगे सामान्य कार्यकर्ता उसकी गोलियों के शिकार होते रहे हैं।

आज पुनः मार्क्सवाद के सामाजिक व्यवहार के पक्ष को स्थापित करने की आवश्यकता है। भारतीय तथा विश्व क्रांतिकारी आंदोलन में कई बुद्धिजीवियों, संगठनों के व्यवहार के पक्ष से हटने के कारण विभिन्न किस्म के भटकाव जन्म ले रहे हैं। इनमें प्रमुख हैं—पंडित्य-प्रदर्शनवाद, निष्क्रिय उग्र-परिवर्तनवाद, सुधारवाद, एक ही तरह से एक ही तरीके से वर्षों निरर्थक कार्यों में लगे रहना, औपचारिक ढंग से विचारधारा का झण्डा उठाना परन्तु व्यवहार में न उतरना इत्यादि। इन सभी बीमारियों से तभी निजात मिल सकती है, जब क्रांतिकारी सिद्धांत के अनुरूप आवश्यक क्रांतिकारी व्यवहार किया जाय।



अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन के बारे में

हमारे देश का कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन पिछले तीन दशकों से एक अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन के लिए प्रयासरत है।

नक्सलबाड़ी किसान उभार के साथ सी.पी.आई. (एम) के नव-संशोधनवादी नेतृत्व के विरुद्ध बगावत करके जो निर्णायक सम्बन्ध विच्छेद हुआ उसका प्रतिफलन एक सही क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के गठन के रूप में नहीं हो पाया। कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों द्वारा अखिल भारतीय तालमेल कमेटी की स्थापना एक सही कदम था लेकिन तालमेल कमेटी को गलत ढंग से पार्टी कमेटी की तरह चलाकर मनमाने व नौकरशाहना तरीके से तालमेल कमेटी से कुछ लोगों को हटा कर तथा बिना तैयारी के व समय से पहले सी.पी.आई. (एम.एल.) का गठन करके बाद में होने वाली फूट व बिखराव के सिलसिले के सारे बीज पहले ही बो दिये गये। दरअसल, सी.पी.आई. (एम.एल.) की 1969 में स्थापना और 1970 में हुई उसकी कांग्रेस “वामपंथी” आतंकवादी कार्यदिशा व संकीर्णतावादी सांगठनिक कार्यदिशा पर आधारित थी। हालांकि यह भी सही है कि सी.पी.आई. (एम.एल.) से बाहर जो क्रांतिकारी कम्युनिस्ट अपेक्षाकृत सही क्रांतिकारी जनदिशा पर अमल कर रहे थे, वे भी टूट-फूट व बिखराव का शिकार हुए।

आज, तीन दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद देश के क्रांतिकारी कम्युनिस्ट एक अखिल भारतीय सर्वहारा पार्टी का गठन नहीं कर सके हैं। यह स्थिति समूचे देश के सर्वहारा वर्ग और मेहनतकश अवाम के मुक्ति संघर्ष की दृष्टि से दुखद लेकिन कठोर हकीकत है। इस समय खुद को सी.पी.आई. (एम.एल.) का असली वारिस कहने वाली कई “पार्टियां” हैं। इसी प्रकार और भी कई कम्युनिस्ट क्रांतिकारी ग्रुप हैं। ये सभी पार्टियां और ग्रुप दरअसल पूर्व पार्टी-संगठन हैं।

इन पूर्व पार्टी-संगठनों के बीच सर्वहारा वर्ग की आज की विचारधारा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के आकलन, भारतीय क्रांति के कार्यक्रम तथा लेनिनवादी सांगठनिक उसूलों के आधार पर अपने पूर्व पार्टी संगठनों को चलाने के सवाल के अलावा सर्वहारा वर्ग के बीच अपने काम को केन्द्रित करने या न करने के बारे में, पार्टी संगठनों के विभिन्न स्तरों पर नेतृत्वकारी निकायों के पेशेवर क्रांतिकारियों से निर्मित होने या न होने के बारे में तथा पार्टी के गुप्त ढांचे के बारे में मतभेद मौजूद हैं। क्रांतिकारी जनदिशा के बारे में भी मतभेद बरकरार हैं। इन बुनियादी किस्म के मतभेदों के कारण ही ये पूर्व पार्टी-संगठन बरकरार हैं। इन मतभेदों का आधार विचारधारा-राजनीति व सांगठनिक उसूलों में है। इसीलिए बिना इन मतभेदों को हल किए एक अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन महज सदिच्छाओं के आधार पर नहीं किया जा सकता।

कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा वर्ग की पार्टी होती है। यह सर्वहारा वर्ग का हिरावल दस्ता होती है। पूर्व पार्टी-संगठन के बतौर कार्य करने वाले संगठन सर्वहारा वर्ग के हिरावल दस्ते हैं। इनमें से ही आगे सर्वहारा वर्ग का सदर मुकाम, अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होगा। सर्वहारा वर्ग के बीच इसका व्यापक आधार होना चाहिए और सर्वहारा वर्ग से आये लोगों से इस पार्टी का अधिकाधिक नेतृत्व व सदस्यता होनी चाहिए। वैसे तो ये बातें कहने की जरूरत नहीं होती लेकिन हमारे यहां कम्युनिस्ट संगठनों के भीतर इस मसले पर भी मतभेद मौजूद हैं। कई कम्युनिस्ट संगठन जुबानी तौर पर तो अपने को सर्वहारा वर्ग की पार्टी के बतौर चित्रित करते हैं

लेकिन अपनी बनावट व जनाधार की दृष्टि से और सर्वोपरि अपने दृष्टिकोण में वे मूलतः गरीब व छोटे किसान या जनजातियों की पार्टी के तौर पर बने हुए हैं। इस भटकाव के विरुद्ध बिना संघर्ष किए और इसे पराजित किये बगैर एक सही कम्युनिस्ट पार्टी का गठन नहीं किया जा सकता।

एक अखिल भारतीय क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के गठन का आधार सर्वप्रथम विचारधारात्मक ही होगा। आज के सही मार्क्सवाद, मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा के बारे में भी मतभेद मौजूद हैं। हमारे आंदोलन में माओ विचारधारा के अभिन्न अंग के तौर पर किसी देश की क्रांति की मंजिल के सवाल को पेश करने की गलत पद्धति मौजूद है। विचारधारा के प्रश्न को कार्यक्रम के प्रश्न के साथ गड़-मड़ करने की प्रवृत्ति बरकरार है। इसके अतिरिक्त “वामपंथी” आतंकवादी कार्यदिशा का मार्क्सवादी समाहार न होने के कारण पार्टी संगठन को संचालित करने में, पार्टी-संगठन व जनसंगठनों के सम्बन्धों के बारे में और जनसंघर्षों और आंशिक संघर्षों के प्रति दृष्टिकोण में गम्भीर “वामपंथी” व दक्षिणपंथी भटकाव मौजूद हैं। कई कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठनों का विचारधारात्मक सवालों के प्रति व समूचे क्रांतिकारी खेमे के प्रति एक अजीबो-गरीब उदासीनता का रूख है जो किसी भी तरह सर्वहारा दृष्टिकोण का परिचायक नहीं है। मजदूर आंदोलन को मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी विचारधारा से अलग करने के पूंजीवादी दृष्टिकोण से प्रभावित कई क्रांतिकारी संगठन ट्रेड-यूनियन आंदोलन में ही संलग्न हैं। विचारधारात्मक क्षेत्र में इस तरह की विच्युतियां क्रांतिकारी कम्युनिस्ट संगठनों को अवसरवादी रूख अपनाते की ओर ले जाती हैं, जो दक्षिणपंथी भटकाव का स्रोत हैं। विचारधारात्मक दृढ़ता के बिना सर्वहारा वर्ग का सर्वोच्च संगठन-कम्युनिस्ट पार्टी संगठन-अपने ऐतिहासिक मिशन को पूरा करने की ओर नहीं जा सकता। इसलिए कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठनों को विचारधारात्मक तौर पर आज के सही मार्क्सवाद, मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा की हिफाजत करनी होगी और विजातीय प्रवृत्तियों और रूझानों को परास्त करना होगा। आज जब कि विश्व पैमाने पर और हमारे देश के स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग और उनके बुद्धिजीवी, मजदूर वर्ग की विचारधारा पर चौतरफा हमला कर रहे हैं और मजदूर आंदोलन के भीतरघाती उनके इस हमले में मदद पहुंचा रहे हैं तो सर्वहारा वर्ग के सर्वोच्च संगठन-कम्युनिस्ट पार्टी का यह दायित्व और भी बढ़ जाता है कि वह इन हमलों का जबाब न सिर्फ खण्डन-मण्डन से दें बल्कि अपने पार्टी संगठनों के निर्माण में तथा जनसंघर्षों को संगठित करने में विचारधारात्मक दृढ़ता पर कायम रहें तथा संशोधनवाद का पर्दाफाश करें। पार्टी संगठन के भूमिगत ढांचे, पेशेवर क्रांतिकारियों की गठी हुई टुकड़ी को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति सर्वहारा दृष्टिकोण पर हो रहे हमलों का दृढ़तापूर्वक विचारधारात्मक अवस्थिति अपनाते हुए मुकाबला किया जाना चाहिए एवं इनको पराजित किया जाना चाहिए। बिना विचारधारात्मक एकता के सही कम्युनिस्ट पार्टी के गठन की कल्पना नहीं की जा सकती।

हमारे देश के कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन में मौजूद फूट और बिखराव की स्थिति के बन रहने में एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि कई संगठनों द्वारा अखिल भारतीय पार्टी के गठन के कार्यभार को केन्द्रीय कार्यभार घोषित करने के बावजूद विचारधारात्मक और अन्य मतभेदों के समाधान के लिए कोई पहल नहीं की जाती या इस कार्यभार को कोई महत्व नहीं दिया जाता। अपने दैनंदिन कार्यों में व्यस्त ये संगठन अखिल भारतीय पार्टी के गठन के कार्यों की अवहेलना करते हैं।

इसके अतिरिक्त, कई संगठनों में यह घातक संकीर्णतावादी प्रवृत्ति मौजूद है कि ये एकता की दुहाई तो देते हैं लेकिन ऐसे किसी प्रयास को यह कह कर खारिज कर देते हैं कि वह प्रयास सफल नहीं होगा। न तो वे

इसके समानान्तर कोई विकल्प देते हैं और न ही वे किसी ऐसे एकता प्रयास में भागीदारी करते हैं। वे एकान्तवासी साधुओं की तरह अपने संगठन को भी बाकी आंदोलन से अलग-थलग बनाये रखते हैं हालांकि उनका दावा यह होता है कि वे एक अखिल भारतीय पार्टी के गठन के कार्यभार को केन्द्रीय समझते हैं। इन संकीर्णतावादी भटकावों को नेस्तनाबूद किए बगैर अखिल भारतीय एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी के गठन की दिशा में आगे नहीं बढ़ा जा सकता।

यहां यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि जहां संशोधनवाद परिस्थिति के बदलने के नाम पर मार्क्सवाद के बुनियादी सिद्धांतों को ही संशोधित कर डालता है, वहीं जड़सूत्रवाद पुराने सूत्रों से परिस्थिति बदल जाने के बावजूद भी चिपका रहता है और कुछ भी नहीं बदला है की रट लगाते हुए जूतों हिसाब से पैर काटता रहता है। हमारे यहां के कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठनों में जड़सूत्रवाद का भी पर्याप्त बोल-बाला है कुछ कम्युनिस्ट संगठनों के लिए तो आज भी साम्राज्यवादी खेमे और समाजवाद के बीच अंतर्विरोध विश्व पैमाने के बुनियादी अंतर्विरोधों में है। कुछ लोग आज भी साम्राज्यवाद के सामाजिक अवलम्ब के तौर पर सामंतवाद को देखते हैं या कुछ लोग साम्राज्यवाद की मूलभूत विशेषता में अभी भी विभिन्न साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा दुनिया का भौगोलिक बंटवारा मानते हैं, ये जड़सूत्रवाद की कुछ मिसालें हैं। कम्युनिस्ट आंदोलन में मौजूद जड़सूत्रवाद भी मतभेद और बिखराव के लिए जिम्मेदार है।

यह जड़सूत्रवाद जब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के आकलन पर लागू किया जाता है तब नतीजे ऐसे अजीबो-गरीब निकलते हैं, जिनसे लगता है कि बदलने के बावजूद दुनिया में कुछ भी नहीं बदला है। कुछ कम्युनिस्ट संगठन, हकीकत में जो साफ-साफ परिवर्तन दिख रहा है, उसको अपने पुराने फ्रेमवर्क में समायोजित करते दीखते हैं हालांकि जिंदगी आगे बढ़ चुकी होती है इसी प्रकार जब इस जड़सूत्रवाद के आधार पर आज की भारतीय समाजव्यवस्था का विश्लेषण पेश किया जाता है तो ऐसा लगता है कि 1947 से लेकर आज तक भारतीय समाज में कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं और वर्गीय संरचना मूलतः जस की तस बनी हुई है।

इस तरह अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के आकलन और भारतीय क्रांति के कार्यक्रम के सवाल पर विभिन्न कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठनों के बीच मतभेद बरकरार हैं। स्वाभाविक है कि इतने व्यापक मतभेदों के मौजूद रहते हुए कोई क्रांतिकारी एकता नहीं हो सकती। इसमें सबसे त्रासद स्थिति यह है कि जिन्दगी के तथ्य जिस हद तक मजबूर कर देते हैं, उसी हद तक उतने तथ्यों को पुराने सूत्रों में फिट किया जाता है, सूत्रों पर पुनः विचार के लिये साथी तैयार नहीं हैं। जब तक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के आकलन और भारतीय क्रांति के कार्यक्रम के सवाल पर कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठनों के बीच एकता नहीं बनती तब तक अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन की समस्या को हल नहीं किया जा सकता।

कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठनों के बीच लेनिनवादी सांगठनिक उसूलों को लागू करने के सवाल पर भी मतभेद हैं, इनमें से कुछ की चर्चा पहले की जा चुकी है। जनवादी-केन्द्रीयता के लेनिनवादी सांगठनिक उसूलों का सिद्धांततः मानने के बावजूद पूर्व पार्टी संगठनों में इसे न लागू कर पाने की मजबूरी बतायी जाती है। यहां स्पष्ट होना चाहिए कि पूर्व पार्टी-संगठन भी ठीक उसी प्रकार जनवादी-केन्द्रीयता के उसूलों पर कायम रहेंगे, जिस प्रकार एक अखिल भारतीय पार्टी कायम रहेगी। आंदोलन के भीतर कहीं जनवाद पर ही जोर है, तो कहीं केन्द्रीयता पर।

सांगठनिक उसूलों के मामले में ये विच्युति है और इसके विरुद्ध संघर्ष कर और इसे पराजित करके ही एक सही पार्टी बनाने की और बढ़ा जा सकता है।

इनके अतिरिक्त, अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाने की दिशा में एक बड़ी बाधा अपनी गलतियों के प्रति जिम्मेदार कम्युनिस्ट दृष्टिकोण का अभाव है। हमारे आंदोलन में गलतियों से चुपचाप पिण्ड छुड़ा लेने की प्रवृत्ति मौजूद है। इसलिए सही सैद्धांतिक समाहार नहीं हो पाता। फलस्वरूप एक भटकाव से दूसरे भटकाव की ओर पेंडुलम की तरह आंदोलन जाने के लिए अभिशप्त होता है। अनेक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठनों के पास न तो “वामपंथी” आतंकवादी कार्यदिशा का ही सैद्धांतिक समाहार है और न ही दक्षिणपंथी लाइन का। चूंकि अपनी गलतियों के प्रति जिम्मेदारी कम्युनिस्ट दृष्टिकोण का अभाव है, इसलिए इन कार्यदिशाओं के बारे में अवसरवादी पहुंच मौजूद रहती है। जब तक विभिन्न कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठनों में, अतीत में अपने द्वारा की गयी गलतियों के प्रति निर्ममतापूर्वक विश्लेषण का अभाव रहेगा और उसकी जिम्मेदार नहीं स्वीकार की जायेगी, तब तक ही सही अर्थों में, अखिल भारतीय पार्टी बनाने में बाधा मौजूद रहेगी।

भारत के कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन के एकीकृत पार्टी में एकजुट होने में ये प्रमुख विचारधारात्मक-राजनीतिक-सांगठनिक बाधाएं हैं। इसके अतिरिक्त अन्य रणनीतिक व रणकौशल सम्बन्धी मतभेद हैं, जिनके आधार इन्हीं उपरोक्त बाधाओं में मौजूद हैं।

यही कारण है कि अतीत में एकता कायम करने के तमाम प्रयास एक अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन तक नहीं पहुंचे। बल्कि कई बार तो एकता प्रस्तावों की स्याही सूखते-सूखते ही वे फिर टूट-फूट व बिखराव के शिकार हो गए। इन बुनियादी प्रश्नों पर, मतभेदों पर पर्दा डालकर या कुछ रणनीतिक व रणकौशलात्मक मामलों में एकता के आधार पर विलय करने के बाद फिर से फूट हो जाने के परिणाम सामने आ चुके हैं।

हमारे सामने उन दम्भपूर्ण दावों का खोखलापन भी मौजूद है, जो अपने को अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तौर पर घोषित करते हैं। ये सभी दावे, कम्युनिस्ट पार्टी गठन की दिशा में अनावश्यक बाधा के तौर पर कार्य करते हैं। इसी प्रकार यह दावा कि इस समय पार्टी-निर्माण ही प्रमुख कार्यभार है, जो आगे चल कर पार्टी-गठन के कार्य को सम्पन्न करेगा, इसी के समतुल्य है कि यह दावा करने वाला संगठन ही आगे चलकर अपने को पार्टी में तब्दील कर देगा। पार्टी-निर्माण और पार्टी-गठन के द्वन्द्वात्मक रिश्तों को न समझ पाने के कारण, ऐसे दम्भपूर्ण दावे किये जा रहे हैं। ऐसे भी अराजकतावादी भटकाव आंदोलन में हैं जो पूर्व पार्टी-संगठनों की मौजूदगी को ही अखिल भारतीय पार्टी बनाने के रास्ते में बाधा समझते हैं। निश्चित तौर पर अखिल भारतीय पार्टी बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए पार्टी-गठन सम्बन्धी इन भटकावों को पराजित करना ही होगा।

यहां यह तथ्य ध्यान में रखना आवश्यक है कि हमारे देश में कम्युनिस्ट आंदोलन का इतिहास पुराना है और यहां अखिल भारतीय पार्टी का गठन कोई ऐसी परिघटना नहीं है जो कम्युनिस्ट आंदोलन के शुरूआती दौर में होती है। न ही इस समय कम्युनिस्ट आंदोलन की वह स्थिति है जो नक्सलबाड़ी किसान उभार के बाद के समय में थी। नक्सलबाड़ी किसान उभार के ठीक बाद के समय में अधिकांश कम्युनिस्ट क्रांतिकारी एक ही पार्टी से विद्रोह करके आये थे। सी.पी.आई. (एम.) के नवसंशोधनवादी नेतृत्व के विरुद्ध विद्रोह करके विभिन्न राज्यों व जिलों से आने वाले कम्युनिस्ट क्रांतिकारी, अखिल भारतीय तालमेल कमेटी में शरीक हुए थे। उस समय उनकी खुद की कोई विचारधारात्मक-राजनीतिक-सांगठनिक अवस्थिति एक ग्रुप के बतौर निश्चित रूप-रंग नहीं लिए हुए थी।

नवसंशोधनवाद के विरुद्ध विद्रोह ही उनकी पहचान थी। आज स्थिति बहुत भिन्न है। अधिकांश कम्युनिस्ट क्रांतिकारी ग्रुप इस लम्बी अवधि में अपनी निश्चित विचारधारात्मक-राजनीतिक-सांगठनिक पहचान बना चुके हैं। वे पार्टी के बतौर अपने पूर्व पार्टी-संगठनों को संचालित कर रहे हैं। ऐसी हालत में, इन पूर्व पार्टी-संगठनों के बीच विचारधारात्मक-राजनीतिक-सांगठनिक संघर्ष को संचालित करने में ज्यादा धैर्य, सूझबूझ का परिचय देना होगा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह कि ऐसे ताने-बाने का निर्माण करना होगा। जिसके जरिए एक अखिल भारतीय क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के गठन का रास्ता प्रशस्त हो कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन के अंदर मौजूद बुनियादी मतभेदों को बिना हल किए हुए, किसी भी किस्म की अवसरवादी एकता के अत्यन्त नुकसानदेह परिणाम हम पहले ही देख चुके हैं।

नक्सलबाड़ी किसान उभार के बाद गठित तालमेल कमेटी की प्रक्रिया एक पार्टी बनाने की दिशा में सही कदम थी। आज भिन्न परिस्थिति में ऐसी ही तालमेल कमेटी को फिर से गठित करके एक अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाने की दिशा में संघर्ष को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस तालमेल कमेटी में आने की पूर्व-शर्त कम से कम यह होनी चाहिए:

- ★ कि संगठन मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा को अपनी पथप्रदर्शक विचारधारा स्वीकार करता हो।
- ★ कि संगठन गुप्त ढांचे और संगठन में पेशेवर क्रांतिकारियों की नेतृत्वकारी कमेटी सहित, पार्टी-संगठन के लेनिनवादी सांगठनिक उसूलों पर अमल करता हो। इन दो न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने वाले संगठनों से मिलकर बनी तालमेल कमेटी को अपने भीतर मौजूद बुनियादी सवालियों पर मतभेदों को हल करने के लिए उपयुक्त तौर-तरीकों को ईजाद करना चाहिए। इन तरीकों में सम्बन्धित संगठनों द्वारा मिलकर एक संयुक्त सैद्धांतिक-विचारधारात्मक पत्रिका निकालना तथा संयुक्त व्यावहारिक कार्यवाहियों को संगठित करने के तौर-तरीके शामिल होंगे।

इस तालमेल कमेटी में शामिल होने वाले प्रतिनिधि अपने संगठनों के सर्वोच्च नेतृत्वकारी निकाय के सदस्य होने चाहिए। तालमेल कमेटी में लिये जाने वाले सारे फैसले सर्वसम्मति से लिये जाने चाहिए। तालमेल कमेटी में लिए गए फैसलों को शामिल संगठनों के लिए बाध्यकारी होना चाहिए।

तालमेल कमेटी में शामिल संगठनों के भीतर द्विपक्षीय या बहुपक्षीय वार्ता को आगे बढ़ाने व यदि सम्भव हो तो दो या ज्यादा संगठनों के बीच एकता कायम होने की स्थिति में विलय का रास्ता खुला होना चाहिए। इसके बाद भी, विलय के बाद का संगठन तालमेल कमेटी का सदस्य बना रहना चाहिए।

यह तालमेल कमेटी मूलतः विभिन्न संगठनों से मिलाकर बनी वह कमेटी होगी जिसका केन्द्रीय कार्यभार अखिल भारतीय पैमाने पर एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होगा। इसका नामकरण तालमेल कमेटी के अलावा कुछ और भी हो सकता है। मूल बात इसके कार्यभार और इसका कार्यक्षेत्र निर्धारित करने की है।

सम्मेलन यह फैसला लेता है कि यदि ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू होती है तो हम पूर्व पार्टी-संगठन के बतौर उसमें अपनी क्षमताभर योगदान करेंगे। हम इस बात की भी सम्भावना तलाशेंगे कि हम अपनी सामर्थ्य भर इस प्रक्रिया को शुरू करने में पहल लें।



फिलिस्तीनी मुक्ति संघर्ष के बारे में

फिलिस्तीनी जनता स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना के लिए विगत पांच दशकों से बहादुराना संघर्ष कर रही है। अमरीकी साम्राज्यवाद और उसके पिटू इज़रायली शासक फिलिस्तीनी जनता के मुक्ति संघर्ष का क्रूरतापूर्वक गला घोट रहे हैं। अमरीकी सहयोग और समर्थन से इज़रायली टैंक जब-तब फिलिस्तीनी नियंत्रित क्षेत्रों में घुसकर फिलिस्तीनियों के घरों को रौंदते रहते हैं। इज़रायली सेना फिलिस्तीनी जनता की नृशंसतापूर्वक हत्याएँ जारी रखे हुए हैं। इसके बावजूद फिलिस्तीनी जनता अपनी मुक्ति की आकांक्षा और अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान की खातिर अभी भी दृढ़तापूर्वक मैदान में डटी हुई है।

फिलिस्तीनी जनता के विगत संघर्षों का इतिहास कई उतार-चढ़ावों से भरा रहा है। इज़रायल-अमेरिकी दमन के खिलाफ अरब देशों का समर्थन फिलिस्तीनी जनता को मिलता रहा था। परंतु जैसे-जैसे अरब देश अमेरिकी प्रभुत्व को स्वीकारते गये हैं वैसे-वैसे अरब शासक इस संघर्ष के साथ विश्वासघात करते गये हैं। अमेरिकी दबाव में कई अरब देशों ने इज़रायल के साथ संधियां सम्पन्न कर लीं, जिसके कारण अमेरिका अरब देशों की इज़रायल के खिलाफ एकता को तोड़ने में सफल रहा। इससे फिलिस्तीनी संघर्ष को धक्का पहुंचा है। हालांकि अरब जनता आज भी फिलिस्तीनी जनता के मुक्ति संघर्ष के साथ खड़ी है।

पहले सोवियत संघ और बाद में चीन में पूंजीवादी पुनर्स्थापना से फिलिस्तीनी जनता के मुक्ति संघर्ष को धक्का लगा। बाद के दिनों में सोवियत साम्राज्यवाद और अमेरिकन साम्राज्यवाद के बीच के अन्तर्विरोध के अमेरिकी साम्राज्यवाद के पक्ष में हल हो जाने से बने शक्ति संतुलन ने उसकी आक्रामकता को बहुत बढ़ा दिया है। इसने फिलिस्तीनी जनता के मुक्ति संघर्ष को और भी दुरुह बना दिया है। इस बदल गये शक्ति संतुलन और तीसरी दुनिया के शासकों के विश्व साम्राज्यवादी व्यवस्था के साथ एकाकार हो जाने से जो समर्थन व सहयोग पहले मिलता था। वह आज कहीं भी दिखायी नहीं देता। स्वयं भारतीय शासक वर्ग भी फिलिस्तीनी जनता के संघर्ष को समर्थन देने के बजाय इज़रायली शासकों के साथ राजनैतिक-आर्थिक-सामरिक सहयोग की ओर उन्मुख हो रहा है।

इन नयी परिस्थितियों में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता यासर अराफात ने भी समझौतापरस्ती का रुख दिखाया है। अमेरिकी दबावों के आगे झुकते हुए फिलिस्तीन ने ओस्लो समझौता किया। इस समझौते के परिणामस्वरूप ही फिलिस्तीन को सीमित स्वायत्तता मिली थी। परंतु इज़रायली शासकों ने एक दशक से भी कम में ही इस समझौते की धज्जियां उड़ा दी हैं, वे कभी भी इस समझौते को लागू करने के प्रति गंभीर नहीं रहे।

इन विपरीत हालातों के बावजूद भी फिलिस्तीनी जनता ने अपने अभूतपूर्व साहस से दूसरे इतिहादा की शुरुआत की। धुर दक्षिणपंथी एरेल शेरोन की हिंसात्मक कार्यवाहियों के खिलाफ फिलिस्तीनी जनता अपने प्रतिरोध को आगे बढ़ा रही है। फिलिस्तीनी जनता के वहशियाना दमन के कारण ही आज फिलिस्तीन के लोग फिलिस्तीनी राष्ट्र के सपने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। द्वितीय इतिहादा के शुरु होने के बाद से खुद इज़रायली जनता ने फिलिस्तीनी जनता पर ढाये जाने वाले जुल्म की खिलाफत की है तथा अपने शासकों का विरोध किया है। इज़रायली जनता ने आगे बढ़कर इज़रायली सेना को फिलिस्तीनी गांवों में घुसने से रोकने के

प्रयास किये हैं। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि इज़रायली सैनिकों में इज़रायली शासकों द्वारा फिलिस्तीनी जनता की हत्याओं के सिलसिले को जारी रखने के खिलाफ आक्रोश उभरा है तथा कुछ ने ड्यूटी करने से इन्कार कर दिया। इज़रायली जनता और साहसी सैनिकों की फिलिस्तीनी जनता के साथ यह एकजुटता इस बात का सबूत है कि इज़रायली जनता व इज़रायली शासकों के बीच दृष्टिकोण में जमीन आसमान का फर्क है। निश्चित ही यदि इज़रायल के भीतर यह विरोध और अधिक बढ़ता है तो इज़रायली शासक वर्ग के लिए फिलिस्तीन पर लम्बे समय तक कहर बरपाना सम्भव नहीं होगा। इज़रायली जनता फिलिस्तीनी जनता के मुक्ति संघर्ष के पक्ष में और अपने शासकों के विरोध में खड़ी होकर ही स्वयं अपने शासकों से अपनी मुक्ति की और अग्रसर हो सकती है। अमेरिकी साम्राज्यवाद ने पिछले दिनों इज़रायली कार्यवाहियों को बहुत खुले रूप में जायज ठहराया है और इज़रायली सैनिक कार्यवाही और रामल्ला की घेरेबंदी के लिए फिलिस्तीन को ही दोषी ठहराने से स्पष्ट हो गया है कि फिलिस्तीनी राष्ट्र का सपना यासर अराफात के अमेरिकी साम्राज्यवाद के आगे घुटने टेकने से पूरा नहीं होगा।

दुनिया की मेहनतकश जनता—यहां तक कि साम्राज्यवादी देशों की जनता भी, अपने शासकों के विपरीत फिलिस्तीनी जनता के संघर्ष का समर्थन करती है और अमेरिकी साम्राज्यवाद के सहयोग और समर्थन से जारी दमन के खिलाफ खड़ी है।

सम्मेलन, इज़रायल द्वारा फिलिस्तीनी जनता की स्वतंत्र राष्ट्र की आकांक्षा को निमर्मतापूर्वक कुचले जाने का विरोध करता है। इसके साथ ही भारतीय शासकों और इज़रायली शासकों के प्रतिक्रियावादी गठजोड़ का विरोध करता है। सम्मेलन, फिलिस्तीनी जनता के अपने राष्ट्र प्राप्ति के लिए चलाये जाने वाले संघर्ष का समर्थन करता है तथा उनके साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करता है।



नेपाल के जनयुद्ध के बारे में

हमारे पड़ोसी देश नेपाल की जनता नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की अगुवाई में जनवादी गणराज्य की स्थापना के लिए शौर्यपूर्ण जनयुद्ध लड़ रही है।

नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) द्वारा जारी जनयुद्ध पिछले वर्ष नेपाल सरकार की छलपूर्ण शांति वार्ताओं को भंग कर देने के बाद आज एक नए मुकाम पर पहुंच गया है।

यह जनयुद्ध नेपाल की निरंकुश राजशाही एवं पूंजीपति वर्ग के गठजोड़ के साथ-साथ भारतीय विस्तारवाद एवं साम्राज्यवाद के खिलाफ भी लक्षित है, जो नेपाली जनता का तीव्र शोषण कर रहे हैं।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ने संशोधनवाद, संसदवाद एवं अवसरवाद से निर्णायक विच्छेद कर क्रांतिकारी विचारधारा की हिफाजत की एवं सर्वहारा का परचम बुलंद किया है।

1996 में जब माओवादियों ने जनयुद्ध की शुरुआत की थी तो नेपाली शासक वर्ग समेत दुनिया भर के प्रतिक्रियावादियों ने इसे क्षणभंगुर घोषित किया था। लेकिन माओवादियों के नेतृत्व में नेपाली जनता का संघर्ष लगातार आगे बढ़ता गया।

क्रांतिकारी विचारधारा, जनदिशा एवं संघर्ष के विभिन्न रूपों के रचनात्मक प्रयोग के द्वारा माओवादी, नेपाली जनता की बहुसंख्यक आबादी को निरंकुश शासन के खिलाफ गोलबंद करने तथा शासकवर्ग के खिलाफ अपनी चुनौती को लगातार मजबूत बनाने में सफल रहे हैं। सागरमाथा के शिखर पर फैली लालिमा से अंधेरे के स्वामियों की रीढ़ में कंपन हो रहा है। जहां नेपाली शासक वर्ग नेपाली क्रांति के ज्वार को देखकर बुरी तरह आंतकित हैं, वही साम्राज्यवादियों एवं भारतीय विस्तारवादियों के माथे पर शिकन साफ दिखाई दे रही है। आज नेपाली शासक वर्ग देश में आपातकाल लागू करके निहत्थी जनता का शाही सेना के द्वारा नृशंस कत्लेआम रचकर नेपाली क्रांति को खून में डुबो देने पर उतारू हैं। आपातकाल की अवधि में नेपाली शासकवर्ग का देशविरोधी-जनविरोधी घृणित चेहरा पूरी तरह बेपर्दा हो गया है। नेपाल के गावों, वनों, खेत-खलिहानों के ऊपर हवाई बमबारी कर नेपाली शासक वर्ग अपनी ही जनता के साथ पूरी तरह शत्रुसेना की तरह व्यवहार कर रहा है। आपातकाल के पिछले छः महीनों के दौरान नेपाली शासक वर्ग ने क्रूरता और पाशविकता की सारी हदें पार कर ली हैं। अपने घृणित मंसूबों में नेपाली शासक वर्ग को साम्राज्यवादियों एवं भारतीय विस्तारवादियों का समर्थन तथा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त है। नेपाली क्रांति का गला घोटने के लिए साम्राज्यवादी सरगना संयुक्त राज्य अमेरिका ने नेपाली शासक वर्ग को भारी आर्थिक व सामरिक मदद पहुंचाई है। अमेरिकी सैन्य-सलाहकार सीधे नेपाल की जमीन पर उतरकर प्रत्यक्ष दिशा-निर्देश दे रहे हैं। भारतीय विस्तारवादी भी खुले-छिपे तौर पर नेपाली शासक वर्ग को आर्थिक-सामरिक मदद दे रहे हैं। इस सबके बावजूद नेपाल की बहादुर जनता का क्रांतिकारी संघर्ष

कमजोर नहीं पड़ा है। तमाम संकटों व प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच नेपाली क्रांति अविकल खड़ी है और सर्वहारा के परचम को मजबूती के साथ थामकर मुक्तिपथ पर अग्रसर है।

आज जब पूरी दुनिया में सर्वहारा के संघर्ष पीछे हटे हैं, शोषक व लुटेरी ताकतें एकजुट होकर पूरी दुनिया की जनता पर हमला कर रही हैं, ऐसे में नेपाली क्रांति जनता में नए क्रांतिकारी उत्साह व आशा का संचार कर रही है, उसे अनुप्राणित कर रही है। निस्संदेह आज नेपाली क्रांति का महत्व तप्त मरुस्थल में शीतल जल के समान है।

सम्मेलन, नेपाल की जनता के क्रांतिकारी संघर्ष 'जनयुद्ध' के साथ सर्वहारा की संग्रामी एकजुटता जाहिर करता है तथा नेपाली जनता के क्रांतिकारी संघर्ष में क्षमताभर सहयोग का दृढ़ संकल्प लेता है।



भारत-पाकिस्तान के बीच युद्धोन्माद के बारे में

दक्षिण एशिया में इस समय युद्धोन्माद का माहौल है। भारत और पाकिस्तान की करीब 15 लाख सेनाएं सीमा पर आमने-सामने खड़ी हैं और दोनों के शासक वर्ग लगातार युद्ध की फिजा बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस समय दोनों देशों के बीच युद्ध की सम्भावनाएं सीमित हैं तब भी युद्ध का यह माहौल भारत-पाक सहित अमरीकी साम्राज्यवादियों के दक्षिण एशिया में आपसी सम्बन्धों को एक नयी जमीन में खड़ा कर रहा है।

युद्ध अन्य साधनों से राजनीति का ही जारी रूप है। भारत और पाकिस्तान के शासक वर्ग भी युद्ध की फिजा बनाकर शांतिकाल की अपनी राजनीति को ही आगे बढ़ा रहे हैं और अपने-अपने वर्गीय हितों के हिसाब से चालें चल रहे हैं। अपनी बारी में अमरीकी-ब्रिटिश साम्राज्यवादी भी दक्षिण एशिया में अपनी गोटी सेट कर रहे हैं।

भारत दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी शक्ति है। विश्व के पैमाने पर भी यह एक क्षेत्रीय ताकत बनता है। यही चीज भारतीय शासक वर्ग में क्षेत्रीय विस्तारवाद की महत्वाकांक्षाएं पैदा करती है। दक्षिण एशिया में भारतीय शासक वर्ग की इस क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा को केवल पाकिस्तानी शासक वर्ग ही चुनौती दे पाता है क्योंकि बाकी देश भारत के मुकाबले में अत्यन्त कमजोर हैं। श्रीलंका-बांग्लादेश समेत सभी अन्य देश भारतीय विस्तारवाद के शिकार हैं। नेपाल, भूटान और मालदीव की स्थिति तो अत्यन्त दयनीय है।

पहले भारतीय शासक वर्ग क्षेत्रीय विस्तारवाद की इस महत्वाकांक्षा को सोवियत साम्राज्यवादियों की मदद से आगे बढ़ाता रहा था। नब्बे के दशक की शुरुआत में इसके पतन के बाद भारतीय शासक वर्गों ने दुनिया में उभरते नये शक्ति संतुलन के अनुरूप अपने हितों को ढालना शुरू किया। इन्होंने अमरीकी साम्राज्यवादियों से नजदीकी सम्बन्ध बढ़ाने शुरू किए और उससे क्षेत्रीय शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने की कोशिश की।

11 सितम्बर की घटना से इस प्रक्रिया को नया आवेग मिला। अमरीकी शासक वर्गों के आतंकवाद विरोध के बहाने को इसने भी इस्तेमाल किया और इसके माध्यम से दक्षिण एशिया में अमरीका का विश्वस्त सहयोगी बनने का प्रयास किया। यह इसके क्षेत्रीय विस्तारवाद में अत्यन्त सहायक होता।

परन्तु अमरीकी साम्राज्यवादियों के दक्षिण एशिया में अपने एजेन्डे हैं। वे मध्य व दक्षिण एशिया दोनों में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाना चाहते हैं। मध्य एशिया के तेल व गैस भण्डार इसमें अन्य कारकों के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

अमरीकी साम्राज्यवादियों के अपने इस एजेन्डे में अभी तत्काल पाकिस्तानी शासक वर्ग ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए उन्होंने भारतीय शासकों के प्रस्ताव को भी एक हद तक ही स्वीकार किया। दूसरी, यह बात भी महत्वपूर्ण है कि भारत एक बड़ी शक्ति है और इसके अतीत को देखते हुए अमरीकी साम्राज्यवादी आश्वस्त नहीं

हो सकते कि भारतीय शासक वर्ग हमेशा विश्वसनीय ही रहेगा, कि अपने हितों के लिए वह कभी इराक नहीं बनेगा।

पाकिस्तानी शासक वर्ग अमरीकी साम्राज्यवादियों और भारतीय शासक वर्ग के बीच के इस समीकरण और इनकी चालों के अनुरूप खुद अपने हितों के लिए लगातार चेष्टारत् है । वह लगातार ही भारतीय विस्तारवाद को टक्कर देने के लिए प्रयास करता रहा है। पहले अमरीकी साम्राज्यवादियों से प्रगाढ़ सम्बन्ध और अफगानिस्तान में तालिबान को खड़ा करना इसी के अंग थे। कश्मीर समस्या में उसका हस्तक्षेप भी इसी रणनीति का हिस्सा है।

वर्तमान युद्धोन्माद इसी समीकरण को एक नये घरातल पर पहुंचाने की कोशिश है। इसमें भारतीय शासक वर्ग पाकिस्तानी शासकों को दबाव में लेकर अपनी क्षेत्रीय हैसियत को और बढ़ाना चाहता है। अमरीकी साम्राज्यवादी किसी भी तरह से भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव का इस्तेमाल कर दक्षिण एशिया में जम जाना चाहते हैं। पाकिस्तानी शासक वर्ग इस स्थिति में अपने हितों को बचाने की फिराक में है। अफगानिस्तान में अमरीकी साम्राज्यवादियों के समीकरण इस मामले में उसका सबसे बड़ा उत्तोलक है, जिसका वह दक्षता से इस्तेमाल कर रहा है।

रूसी साम्राज्यवादी और चीन जैसी एशियाई शक्ति भी दक्षिण एशिया में उभरते इस समीकरण में अपनी-अपनी गोटी बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तनाव का लाभ उठाकर विभिन्न साम्राज्यवादी तथा अन्य देश भी हथियार बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं।

भारतीय-पाकिस्तानी शासकों का यह युद्धोन्माद न तो आतंकवाद समाप्त करने को लेकर है और न ही कश्मीर समस्या को हल करने के लिए। ये दोनों ही वर्तमान युद्धोन्माद के लिए बहाने हैं। हां, इस बीच यदि इससे भारतीय शासकों को कश्मीर में थोड़ी राहत मिल जाती है तो यह उनके लिए अतिरिक्त फायदा होगा।

इस युद्धोन्माद से भारत पाकिस्तान दोनों के शासक वर्ग एक और फायदा उठा रहे हैं। वे न केवल युद्धोन्माद के अपने असली मंसूबों को दिखा रहे हैं बल्कि पड़ोसी देश के खिलाफ अंध राष्ट्रवाद फैलाकर जनता को अपने पक्ष में कर ले रहे हैं। जनता अपनी असली मुसीबतों को भूलकर उनके पीछे लग जा रही है। वह अपने शासकों के खिलाफ विद्रोह करने की सोचने के बदले उसके पीछे लामबन्द हो जा रही है।

इस स्थिति में भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वहारा का यह कर्तव्य बनता है कि वे अपने शासकों के असली मंसूबों को समझें और फिर उसका भंडाफोड़ करें। वे अपने शासकों के पीछे खड़े होने के बदले दूसरे देश के सर्वहारा के साथ एकजुट हों और फिर दोनों देशों की सारी जनता का आहवान करें कि वह अपने-अपने शासकों के खिलाफ उठ खड़ी हो और उनके साथ-साथ अमरीकी-ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को भी धूल चटा दें।



गुजरात नर-संहार पर

भूकंप की विनाशलीला तथा सरकारों की तुच्छ एवं पक्षपातपूर्ण राहत कार्यवाही को झेल रही गुजरात की जनता को एक बार फिर हिन्दू फासिस्ट ताकतों के बर्बर सामूहिक हमलों को झेलना पड़ रहा है। सरकारों तथा शासक वर्गीय पार्टियों द्वारा गुजरात दंगे के नाम से प्रचारित किये जा रहे इन पाशविक हत्याकांडों में दो हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जिसमें सैकड़ों को उनके घरों में जिन्दा ही जला दिया गया है। भीषण अग्निकांडों व लूट में अन्य दसियों हजार बेघर व बेरोजगार हो रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चों तथा औरतों को भी नहीं बख्शा गया है तथा फासिस्टी गुंडों द्वारा इनकी सरेआम नृशंसता से, हत्यायें की जा रही हैं।

गुजरात की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा आर.एस.एस., विहिप व बजरंगदल आदि के प्रवक्ताओं ने गोधरा कांड की स्वाभाविक प्रतिक्रिया कह कर इस नर-संहार को औचित्यपूर्ण बताने की कोशिश की। इन्हीं फासिस्ट-संघी ताकतों ने यह एक बार पुनः खुले आम दुहराया कि भारत देश में मुसलमानों को आम सुख-शांति के लिए हिंदुओं की सद्भावना अर्जित करनी चाहिए।

इस सबके साथ-साथ जब अहमदाबाद आदि शहरों में यह लोम हर्षक कांड अपने चरम पर थे तब पुलिस व सशस्त्र बल नदारद थे। कहीं-कहीं पर तो पुलिस, हत्यारों की कार्यवाहियों में शामिल रही। कातिलों व लुटेरों को पहले से पूरा पता था कि उनके खिलाफ कुछ भी नहीं होना है। उनकी सरकार उनके साथ खड़ी है। सेना जैसे सशस्त्र बलों की भी शीघ्र तैनाती में विलम्ब किया गया ताकि अल्पसंख्यकों व अन्य इंसाफ पसंद लोगों पर नरेन्द्र मोदी की 'स्वाभाविक प्रतिक्रिया' को निरावरोध अंजाम दिया जा सके।

इस नर-संहार, आगजनी तथा लूट के जिम्मेदार अपराधियों को गिरफ्तार कर सजा दिये जाने की आम जनता की मांग के साथ भी विपक्षी पार्टियां नहीं खड़ी हुईं। बल्कि, इस पूरे कांड को 'नरेन्द्र मोदी हटाओ' के रूप में सीमित करके उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया।

गुजरात नर-संहार, परम्परागत साम्प्रदायिक दंगे नहीं हैं। यह नर-संहार, मस्जिद ध्वंस तथा मंदिर निर्माण की लहरों पर चल कर सत्तासीन होने वाले फासिस्टों संघ परिवार-भाजपा, विहिप आदि को सोची-समझी कार्यवाही थी जिसे राज्य द्वारा प्रायोजित किया गया।

इस तरह के पूर्व विचारित तथा राज्य प्रायोजित नर-संहार के और आगे भी कभी भी कहीं भी फूट पड़ने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि शासक वर्ग को सत्ता में बने रहने के लिए जनता का ध्यान गरीबी, बेरोजगारी, बदहाली व बीमारी जैसी मूल समस्याओं से हटाये रखना जरूरी है, इसके लिए जनता को साम्प्रदायिकता जैसे पुराने-पिछड़े मूल्यों के विवादों में उलझाये रखना उनकी मजबूरी है। इन्हीं मूल्यों के आधार पर ही वे अपनी चुनावी गणित भी हल करते हैं।

गुजरात नर-संहार तथा अन्य साम्प्रदायिक दंगों के जिम्मेदार वर्तमान पतित शासक पूंजीपति वर्ग व उसकी सरकार तथा पार्टियां हैं। इसका पूरा भंडाफोड़ किया जाना जरूरी है। शासक वर्गों द्वारा धर्म आधारित राजनीति की

जा रही है तथा धर्माधिकारियों के साथ मिलकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी जा रही हैं। धर्म का व्यावसायीकरण करके धन वसूली का साधन बना लिया गया है। आधुनिक समाज में यह एक आपराधिक कार्यवाही है। जिसके अपराधियों को कठोर दण्ड दिया जाना होगा तथा इस पर पूर्ण रोक लगानी होगी। धर्म-निरपेक्षता जिसकी 'सर्व-धर्म समभाव' के रूप में व्याख्या की जाती है, से साम्प्रदायिकता की समस्या हल नहीं हो सकती। इसके लिए धर्म को राजनीति से पूर्णतः विलग करना होगा। धार्मिकता के दुरुपयोग को भी तभी रोका जा सकता है जब धर्म को धनअर्जन के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर पूर्ण रोक लगायी जाय। धार्मिक विश्वास एक व्यक्ति का निजी मामला हो सकता है और इसकी पूरी छूट होनी चाहिए। साथ ही इस हत्यारी पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ एकताबद्ध होकर संघर्ष में कूद पड़ना होगा ताकि इसे ध्वस्त किया जा सके एवं समाजवादी व्यवस्था कायम की जा सके जिसके अन्तर्गत ही मानव द्रोही त्रासदियों से निजात पायी जा सकती है।



